संख्या: 43/2019/521/छप्पन-2019-01/2016 T.C.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ हवाई पट्टी के ओ०एल०एस० रिपोर्ट के अतिरिक्त चिन्हित विद्युत् विभाग संबंधी अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 657/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 25 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ हवाई पट्टी के ओ0एल0एस0 सर्वे रिपोर्ट तथा जनरल मैनेजर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कुल लागत रू0 1,93,76,455/- पर प्रशासकीय अनुमोदन तथा रू0 1,48,14,761/- (रूपए एक करोड़ अड़तालीस लाख चौदह हजार सात सौ इकसठ मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 137/2018/2124/छप्पन-2018-01/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा ओ०एल०एस० रिपोर्ट में चिह्नित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कुल आगणन की धनराशि रु0 1,06,11,931/- के अन्तर्गत विद्युत् विभाग के आगणन की धनराशि रू0 45,61,694/- पर प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि निर्गत की जा चुकी है | अत: निदेशक, नागरिक उड्डयन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2019 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार आगणन की धनराशि रू0 1,93,76,455/- में से पूर्व के शासनादेश दिनांक 14 दिसंबर, 2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि, जिसमें विद्युत पोल से संबंधित धनराशि रू0 45,61,694/- को हटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 1,48,14,761/- (रूपया एक करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार सात सौ इकसठ मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है |

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ हवाई पट्टी के ओ०एल०एस० रिपोर्ट के अतिरिक्त चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु रू0 1,48,14,761/- (रूपए एक करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार सात सौ इकसठ मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रू0 1,48,14,761/- (रूपए एक करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार सात सौ इकसठ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है |

III. जिलाधिकारी, अलीगढ़ और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनरल मैनेजर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य किया जाए|

IV. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

V. किसी कार्य का आगणन रू0 05 करोड़ से कम होने पर प्रयोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण नहीं किया जाता है और रु0 05 करोड़ तक आगणन पर अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित है | नागरिक उड्डयन विभाग में उक्त प्रस्तुत आगणन का परीक्षण करने की तकनीकी दक्षता उपलब्ध नहीं है | अत: शासन द्वारा आगणन का तकनीकी और मात्रात्मक द्रष्टि से परीक्षण नहीं किया गया है | कार्यदायी संस्था, निदेशक व जिलाधिकारी द्वारा उक्त बिन्दुओं के द्रष्टिगत औचित्य सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार प्रश्नगत कार्य कराया जाएगा |

VI. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा |

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,48,14,761/- (रूपया एक करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार सात सौ इकसठ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

5- कृपया रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, अलीगढ़ से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे ।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 43/2019/521(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, अलीगढ़ ।
(4) जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़ ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।